



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2009/भाद्र 31, 1931

No. 306]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2009/BHADRA 31, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2009

सं. 12/2009—2014

फा. सं. 01/94/180/प्रक्रिया पुस्तक-09-10/एएम-10/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा, प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1), 2009—2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

1. पैराग्राफ 4.46 के पहले वाक्य के बाद, निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:—

“तथापि, यदि आवेदन बी आर सी के साथ प्रस्तुत किया गया है तो जिस पोत लदान के लिए दावा किया गया है, प्रस्तुत करने की समयावधि निर्यात की तारीख से 12 महीने अथवा निर्यात आय प्राप्त करने की तारीख से 6 महीने अथवा डीजीएफटी वेबसाइट में ई.डी.आई. शिपिंग बिल के ब्यौरे की अपलिकिंग की तारीख अथवा शिपिंग बिल की प्रिन्टिंग/रिलीज की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, होगी।”

2. पैराग्राफ 4.54 को हटाया जाता है।

3. पैराग्राफ 4.7.5 के पहले उप पैराग्राफ के अंत में, निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:—

“परियोजना आपूर्तियों हेतु, मानदण्ड समिति के निर्णय के मद्दे अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की समय सीमा नए मानदण्ड समिति के निर्णय की सूचना की तारीख से एक वर्ष होगी।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 22nd September, 2009

No. 12/2009—2014

F. No. 01/94/180/HBP-09-10/AM-10/PC -4.—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Police, 2009—14, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1), 2009—2014 :—

1. After the 1st sentence of Paragraph 4.46, the following sentence shall be added :—

“However, in case the application is filed along with BRC, the time period for filing shall be within a period of twelve months from the date of exports or six months from the date of realisation of export proceeds or the date of up-linking of EDI shipping bill details in the DGFT website or within three months from the date of printing/ release of shipping bill, whichever is later, in respect of shipments for which claim has been filed.”

2. Paragraph 4.54 stands deleted.

3. At the end of first sub-paragraph of paragraph 4.7.5, the following sentence shall be added :—

“For project supplies, the time limit for filing representations, if any, against the decision of Norms Committee shall be one year from the date of communication of decision of the Norms Committee.”

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.